

प्रपक,

प्रभात कुमार सारंगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संवासे,

कुल सचिव,
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय,
हरिद्वार।

माध्यमिक शिक्षा/संस्कृत अनुभाग-4

देहरादून:दिनांक: 24 अप्रैल, 2009

विषय:- वित्तीय वर्ष 2009-10 में दिनांक 01-04-2009 से दिनांक 31-07-2009 तक लेखानुदान के माध्यम से स्वीकृत संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग -1 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 205/XXVII (1)/2009 दिनांक 25 मार्च 2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 में उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु रु० 10200 हजार (एक करोड़ दो लाख मात्र) की धनराशि को इस प्रतिबन्ध के साथ आपके निर्वहन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा आवश्यक वचनबद्ध मदों में मजदूरी, विद्युत देय, जलकर, किराया, पेंशन, औषधि, भोजन व्यय, पेट्रोल, टेलीफोन तथा अन्य आवश्यक व्ययों का भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु किया जायेगा। उक्त मदों से भिन्न मदों एवं समस्त चालू निर्माण कार्य, नये निर्माण कार्य, उपकरण व सयंत्र का क्रय तथा वाहन क्रय की स्वीकृतियों के प्रस्ताव पूर्ण औचित्य सहित शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे।

2. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही नियोजन विभाग द्वारा आवंटित परिव्यय की सीमा तक किये जाने का दायित्व आपका होगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग चालू वर्ष की नई मदों के क्रियान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/शासनादेशों के तहत निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जायेगा:-

(i) योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

- (ii) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृति धनराशि को किसी ऐसी मद पद व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुरितका तथा बजट मैनुवल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।
- (iii) आतिरेक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।
- (iv) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय।
- (v) मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।
- (vi) व्यय सम्बन्धीजो भी बिल कोषाधिकारीकोभुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायउनमें, लेखाशीर्षककेसाथ-साथ अनुदान संख्याका भी उल्लेख किया जाय।
- (vii) स्वीकृत धनराशि की जिलावार फाँट सम्बन्धित जिलों एवं शासन को तीन दिन के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (viii) वित्तीय वर्ष 2008-09 में इसके पूर्ववर्ती वर्षों के एरियर भुगतान यदि कोई हो, के विवरण की सूचना अलग से रखी जाय।
- (ix) अप्रैल 2007 से नये पदों के भरे जाने के फलस्वरूप होने वाले व्यय के सापेक्ष श्रेणीवार पदों (समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ') की सूचना रखी जाय।
- (x) व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुरितका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- (xi) निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर समक्ष अधिकारी की टैक्निकल स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यों की लक्ष्य के अनुसार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा/अनुश्रवण अनिवार्य रूप से किया जाय।
- (xii) किसी अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि का बगैर शासन की सहमति के किसी भी प्रकार से पुनर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिन्ध है।
- (xiii) बजट मैनुवल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जानी वाली सूचना समय से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (xiv) बाह्य सहायतित परियोजनाओं, अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत आवंटित परिव्यय के सापेक्ष बजट प्राविधान को अन्य योजना हेतु व्यावर्तित न किया जाय।
- (xv) किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार कय प्रक्रिया (स्टोर परचेज रूल्स), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय संग्रह खण्ड-पांच भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(xvi) छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के लागू होने के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2009-10 में देय 30 प्रतिशत एरियर की धनराशि, जो कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि खाते में डाली जानी है, का भुगतान 01 अप्रैल, 2009 से 31 जुलाई, 2009 तक के लेखानुदान द्वारा प्राविधानित धनराशि से नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष 2009-10 में देय 40 प्रतिशत वेतन एवं भत्तों के एरियर की धनराशि यदि किसी कारणवश सामान्य भविष्य निधि खाते में नहीं डाली जा सकी हो तो उसका भुगतान भी माह जुलाई, 2009 के बाद ही किया जायेगा। यह प्रतिबन्ध संवानिवृत्त होने वाले अथवा अन्य कारणों से सेवा में बने न रहने वाले कार्मिकों के सम्बन्ध में नहीं रहेगा।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय-भार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-10 के अनुदान संख्या-11 के अधीन लेखाशीर्षक -2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-102- विश्वविद्यालयों को सहायता-06-संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-09/ (P)/ XXVII (3)/ 2009-10 दिनांक -20/04/09 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

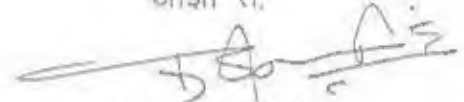

(प्रभात कुमार सारंगी)
सचिव।

संख्या ~~३~~ ३ (1) / XXIV-4 / 2009 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
3. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
4. कुलपति उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार।
5. कुलपति, हे० न० बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल।
6. कुलपति, कुमायूँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
7. राधिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार
7. मण्डलीय अपर/संयुक्त निदेशक संस्कृत शिक्षा, गढ़वाल मण्डल
पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
8. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी।
- ✓ 10. निदेशक एन०आई०सी० उत्तराखण्ड।
11. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-3 उत्तराखण्ड शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



((कवीन्द्र सिंह)

अनुसचिव।